



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 1983/आषाढ़ 7, 1905

No. 106]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 1983/ASADHA 7, 1905

इस भाग में भिन्न प्रकाशन की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

*Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation*

### शाणिज्य मंत्रालय

भारत आयात नियन्त्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 21-आईटी०सी० (पी०एन०)/83

नई दिल्ली, 28 जून, 1983

विषय: 1982-83 के लिए येन 1.5 विलियन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पत की छड़ों और पत्तनों पर माल लाने-ले-जाने के लिए उनकी आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस दर्ते।

मिसिल सं. आई०पी०सी०/23/2/83.—1982-83 के लिए जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पत की छड़ों और पत्तनों पर माल लाने-ले-जाने के लिए उनकी आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए येन 1.5 विलियन दिनांक 1-2-1983 जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी करने के लिए लागू थर्ड और फॉर्थ पत्तनों में यातायात की आवश्यक उनकी सेवाओं के आयात के लिए जापानी संभरकों को वित्तीय भुगतान के लिए किया जाएगा। नह अनुदान सहायता 31-3-1984 तक बंध है।

पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक  
आयात-नियंत्रण

शाणिज्य मंत्रालय, सार्वजनिक सूचना सं. 21-आईटी०सी० (पी०एन०)/83  
दिनांक 28 जून, 1983 का परिचाप्त

1982-83 के लिए येन 1.5 विलियन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पत की छड़ों और पत्तनों की यातायात के लिए आवश्यक उनकी सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस दर्ते।

### खंड-1 सामान्य दर्ते:

(1) 1982-83 के लिए येन 1.5 विलियन (लागत एवं भाड़ा) की जापानी अनुदान सहायता का उपर्योग भारतीय इस्पत प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा भारत में छोटे आकार की इस्पत की छड़ों और पत्तनों में यातायात की आवश्यक उनकी सेवाओं के आयात के लिए जापानी संभरकों को वित्तीय भुगतान के लिए किया जाएगा। नह अनुदान सहायता 31-3-1984 तक बंध है।

(2) बैंक और इंडिया ट्रॉकियो की भुगतान किए जाने वाले सभी बैंक प्रधार सामान्य बैंक प्रणालियों के माध्यम से प्रेपित किए जाएंगे। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन का भुगतान, यदि कोई हो तो, भारत में अधिकर्ता को भारतीय रूपए में किया जाना चाहिए।

(3) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत इस्पत की छड़ों और उपर्योगी सेवाओं की अधिप्राप्ति केवल जापान से ही की जाएगी।

1(4) संविदा में भुगतान को अवश्यक नकद आधार अवैध बैंक औंक इंडिया, टोकियो की जापानी संभरको द्वारा लदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर करना चाहिए। वितरण की अवधि निम्न प्रकार से होनी चाहिए—  
“वितरण 15-3-1984 तक पूर्ण हो जाना चाहिए”।

1(5) संविदा का मूल्य (केवल लागत एवं भाड़े के आधार पर) येन में (येन का अंश हटा देना चाहिए) प्रवर्शित किया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो, भारतीय अधिकारीय कमीशन निकाल देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भारतीय अधिकारीय का मूल्य किसी अन्य सुना में प्रवर्शित नहीं किया जाना चाहिए। जहाज पर्यावरण ने शुल्क लागत एवं भाड़ा राशि अलग से वर्षाई जानी चाहिए, किन्तु संविदा में यह स्वतं स्पष्ट होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा अथवा उसमें वर्णया गया भाड़ा वास्तविक खर्चों के अतिक्रम भुगतान की गणि होगा।

1(6) क्रम संविदा जापानी राष्ट्रियों के साथ केवल जापानी येन में की जानी चाहिए। छंड-2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान स्पष्ट रूप से समाविष्ट होने चाहिए—

2(1) ठेके की अवश्यका 1982-83 के लिए येन 1.5 विलियन के अनुशान सहायता के अनुभार भारत और जापान की सरकारों के बीच 1 फरवरी, 1983 का हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और दसों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2(2) संभरको को भुगतान 'भुगतान के प्राधिकार' (ए/पी) के माध्यम से किए जाएंगे। जो 1982-83 के लिए जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत बैंक औंक इंडिया, टोकियो के लिए सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आधिकारीय कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएंगी।

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होनी जो एक भौत भारत सरकार एवं भूसरी और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होती है।

2(4) जापानी संभरक भारतीय द्रूतावास, टोकियो के परामर्श पर प्राप्त परिवहन अवश्यका करने के लिए सहमत ही और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय द्रूतावास, टोकियो को शामिल भाल की भुवर्येंगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और प्राप्त लदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय द्रूतावास को सूचना देगा। जिससे कि उचित अवश्यका हो सके। विशेष भागलों में, जहाँ आयातक इच्छक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक भौतिक वितरण के अनुबंध आवश्यक अपैर देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय द्रूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

छंड-3 भारत और जापान की सरकारों द्वारा ठेके का अनुमोदन—

3(1) जैसे ही आवेदनों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, आयातक को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित् ठेके की घार प्रतियों जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रम अविद्या के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण अविद्या की घार प्रतियों द्वारा अपैर से पूर्ण कोटों प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र में "(ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन" की 2 कोटों प्रतियों अवर संविधि (टी.ए) आधिकारीय कार्य विभाग, विस मंत्रालय, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय अस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आवधियों से उत्तम सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (अर्थात्) जापान अनुभाग 1982-83 के लिए 1.5 विलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन विस्तारान देने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक सैट सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के द्रूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार के टेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आधिकारीय कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक का जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आधिकारीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू.सी.ओ बैंक विल्डिंग, सप्तम मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जोकि जापानी संभरक की भुगतान करने के लिए बैंक औंक इंडिया टोकियो की अनुबंध 2 के अनुभाग एक "भुगतान प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रसिद्धि भारत का द्रूतावास टोकियो, आयातक के आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आधिकारीय कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) प्राप्त करने पर बैंक औंक इंडिया, टोकियो जापान सरकार, भारत का द्रूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से जापानी संभरक की अवधि कराएगा।

3(5) पोतस्वान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी से उल्लिखित दस्तावेज बैंक औंक इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक औंक इंडिया, दस्तावेजों में उल्लिखित अनुराग को जापानी संभरक को अपने बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान की अवश्यका करने के लिए बैंक औंक इंडिया, टोकियो की देश बैंक और भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए जिन सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से सबद्ध बैंक द्वारा बैंक औंक इंडिया टोकियो को धन परेवित कर के भिन्नीति किया जाएगा।

#### छंड-4 वित्त जमा करने का विधित

4(1) भूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज विप्रवाद रूप से बैंक औंक इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीय हस्त बैंक जो अनुबंध 1 (ठ) में उल्लिखित है, की शाखा होगी। इस बैंक की दस्तावेजों के ये विनियम दस्तावेज केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सबद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक की भुगतान की अवधि अपने बैंकों के धनराशि के बाबत यह अनुबंध गई दिल्ली-4 येन धनराशि के बाबत रूपया विनियमित के अनुसार भारत सरकार के लेखों में जमा करा जिया गया है—

"आयातक अवैध भारतीय इस्पात प्राधिकारण लि० (सेल) आयातित इस्पात की छड़ों की लागत जमा करायेगा जिसकी गणना इस्पात की मूल कीमत के आधार पर होगी, इसमें से आयातक द्वारा चुकाई गई सीधा शुल्क कर की धनराशि घटा दी जाएगी और लागत एवं भाड़ा मूल्य की 4% धनराशि सेवा खर्च के रूप में और अन्य खर्च जैसे संचालन, रेलवे भाड़ा आदि घटा दिए जाएंगे। आयातित इस्पात की छड़ों के लागत एवं भाड़ा मूल्य और आयातक द्वारा ऊपर तथा उल्लिखित वास्तव्य में जमा कराई गई धनराशि दोनों के बीच में आने वाले आलतर के बाद में इस्पात विभाग द्वारा सी.ए.ए.ए.ए को देश सहायता की धनराशि में भागीजित कर दिया जाएगा और 1983-84 के बजाए में लगाया जाएगा। इस्पात विभाग और सी.ए.ए.ए के बीच समजित की जाने योग्य धनराशि पर और भारतीय बैंक टोकियो द्वारा जापानी संभरक को किए जाने योग्य भुगतान के बीच की अवधि के लिए और उनके द्वारा भारत में अपने बैंकों में किए गए बास्तविक निक्षेप की तारीख की अवधि के लिए आयातक को जिसी भी प्रकार का व्याज प्रभार नहीं देना पड़ेगा।"

येन भुगतान के समतुल्य रूपए की गणना करने के लिए अपनाई गई मुद्रा विनियम की वर मुद्रा नियंत्रक, आयात-नियाति की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मुद्रा विनियम की प्रत्यनिति नियंत्रक द्वारा सामय-समय पर मुद्रा नियंत्रक, आयात-नियाति की सार्वजनिक सूचनाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिवर्तोंके साम्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित वरहोगी। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जैसे और जब भी आवश्यक होंगे, अधिसूचित किया जाएगा। संबंध भारतीय बैंक वा इस बात का सुनिश्चय करने का दायित्व होगा कि आयातकों को आयात वस्तवैज संपत्ति से पूर्व देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी गई है। आयातकों यह भी मुनिश्चय करना चाहिए कि अपने बैंकरों से वस्तवैज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी गई है। लेखा शीर्ष जिसमें उपर्युक्त रूपया जमा निक्षेप किया जाएगा वह है “के डिपो-जिट्स एंड एडवांसिंज-843-सिलिंड्रिंजिट्स-फार परवेजिज एटसेट्रा, एमांड-परवेजिज अंडर ग्रांट ऐड फारम दि गवर्नरेंट ऑफ जापान फार 1982-83 ग्रांट फार परवेजिज ऑफ दि स्टोल आइट्स”।

4(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई विली में भा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीस हजारी विली में या यदि, यह सम्भव न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीस हजारी शाखा विली-6 (आवेदिती और प्राप्त) के नाम और उसको देय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसकी सहायक शाखा या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (आवेदित) से ग्राहक डिपो-जिट्स के साम्यम से सरकार के खाते में नकद जमा करानी चाहिए। सार्वजनिक सूचना-184 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-68, सं० 233 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-68 और सं० 132-आईटीसी (पीएन/71) दिनांक 5-10-71 में दृष्टव्य है।

4(3) जालान के विभिन्न कालम भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 को पैरा 2 में निर्धारित सूचना जालान के “छन परेण्य और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण डोरे” कालम में नियमित रूप से निर्विट की गई है। जालान जालान में निम्नलिखित घोरे नियमित रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:-

- (क) वित मंत्रालय के ‘ए/पी’ (भुगतान के लिए प्राधिकारी पद) की सं० एवं विनांक।
- (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की वर के साथ-साथ निक्षेप किए जाने हैं।
- (ग) जापानी संभरक की भुगतान की तिथि।
- (घ) निक्षेप की गई कुल धनराशि।

उसके पश्चात् सी ए ए एंड ए द्वारा जारी किए गए ए/पी(भुगतान के लिए प्राधिकारी पद) का संबंध देते हुए और बींजक तथा पीत परिवहन दस्तवैजों का मंत्रालय करने हुए खजाना चलान, रूपया जमा करने का साक्ष देते हुए पंजीकृत द्वारा सी ए ए एंड ए को भेजा जाना चाहिए।

**टिप्पणी:** भारत में आयातक के बैंकों की यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया, टांकियों में भुगतान की सूचना और नियमित पीत परिवहन दस्तवैजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर स्पष्ट नियमित रूप से जमा कर दिया गया है और यह कि इसके तुरन्त बाद इसकी सूचना सी ए ए एंड ए वित मंत्रालय, (आयिक कार्य विभाग) नई विली को दे दी गई है।

4(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक की लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर स्पष्ट नियंत्रण की धनराशि का पृष्ठाकृत करना चाहिए और अधिसूचित “एम” प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

#### अंड-5 विविध व्यवस्थाएं

##### 5(1) अनुवान सहायता के उपयोग पर रिपोर्ट

आयातकों को पोसलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और देय धनराशि के बारे में ए/वी जारी हो जाने के पश्चात् एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आयिक कार्य विभाग वित मंत्रालय, यूमीओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

##### 5(2) संभरकों की विशेष शर्तें अधिसूचित करना।

आयातकों को इस अनुवान सहायता के अधीन इस्पात की मदों के आयात के सम्बन्ध में उन विशेष प्रावधानों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लेन-देन में संभरक पर प्रभाव डासता हैं।

##### 5(3) विवाद

यह समस्य लेना चाहिए कि आयातकों और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरवायित्व नहीं लेगी। बैंक ऑफ इंडिया, टांकियों द्वारा भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों आयातक द्वारा अनुबंध-1 में “भुगतान को शर्तों” के अन्तर्गत अल्ली तरह से स्पष्ट करनी चाहिए। संविदा को शर्तों में विवाद निपटाने से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

##### 5(4) भविष्य अनुवेश

जापान से 1982-83 के लिए अनुवान सहायता के अधीन आयातों से उत्पन्न या उनके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी भी मामले या सभी मामलों के संबंध में सम्बन्ध समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण, अनुबंधों या आईटीसी को शीर्ष साक्षी दायित्वों का आयातकों को तुरन्त पूरा करना होगा।

##### 5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त अनुच्छेदों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियाति (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कारंबाई की जाएगी।

##### 5(6) अनुबंधों की सूची:-

अनुबंध-1:-ए/पी जारी करने के लिए प्रारंभना पत्र

अनुबंध 2:-ए/पी का प्रपत्र

अनुबंध-1

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रारंभना पत्र”

सं०

दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित मंत्रालय, आयिक कार्य विभाग,

दू०सी०००० बैंक बिल्डिंग, प्रधम मणिल,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ट्रिप्प:- 1982-83 के लिए जापान अनुवान सहायता के अधीन जापान से भारत में छोटे आकार की इसात की छढ़ी और उनके यातायात के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात।

महोब्य,

ऊपर उल्लिखित अनुवान सहायता के अधीन जापान से इस्पात की मदों के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित घोरे - “जैसे हैं जिससे कि आप सम्बद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक ऑफ इंडिया, टांकियों को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें:-

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।  
 (ख) अधिग्राहित के तरीके—क्या यह प्रस्तव छारीद पर अधिग्रहित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्तव के आधार पर किया गया है।  
 (ग) माल का संक्षिप्त विवरण  
 (घ) माल का उत्तम वेश  
 (ङ) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)  
 (च) यदि कोई हो सो भारतीय रूपए में भारतीय एंजेट के कर्मीयां की धनराशि (येन में)  
 (छ) वह कुल लागत नथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।  
 (ज) जापानी सभरको के साथ की गई संविदा की सम्बा और दिनांक।  
 (झ) जापानी सभरक का नाम और पता।  
 (ञ) के भुगतान शर्तों और समावित तिथि जिनको संविदाओं के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।  
 (ट) माल की सुपुर्णी पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथियाँ।  
 (ठ) बैंक आफ इडिया, टाकियो का भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ (प्रत्येक सेट का संख्या और उनके निपटान दर्शाते हुए)।  
 (उ) पोत लावान अनुदेश (अनुमेय या और अनुमेय बाहनन्तरण/आंशिक पात लावान निर्दिष्ट कराजिए)

(ड) भारत में अयातक के बैंक का नाम और पता।

भवदीय,  
अनुबंध-3

स० एक

भारत सरकार

वित मकालय

(आधिक कार्य विभाग)

नई विल्सी, विनाक

सेवा में,

बैंक आफ इडिया,  
टोकियो शाखा,  
टाकियो (जापान)

विषय—1982-83 के लिए यैन 1 5 विलियन की जापान अनुवान सहायता के अधीन छाटे थाकार का/इस्पात की छड़ों के जायात्र के लिए भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

अपके बैंक के साथ . . . . . को किए यह समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एसद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा समरूप छारी के अनुसार संवर्धी को . . . . . येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

१ कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एफी) की पावरी के बारे में सभरको को सूचना दें और इनकी प्रतेरक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, अयातक बैंक, भारत के राजनूतावास, टोकियो और इस मकालय को पृष्ठाकृत की जाए।

३ भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा सकेन्द्रित लावान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

४ आयातक द्वारा आपको दस्तावेज सभरको एवं बैंकरों के प्रभार को भेजने आदि के लिए भाड़े सहित जाया किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े अयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

५ ऐसे ही जापानी सभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लावान दस्तावेज आदि के आधार पर आपके द्वारा कार्ड भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मकालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

६ इन मकालय की विशेष अनुमति के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी सशोषन जारी नहीं किया जा सकता है।

७. यह भुगतान प्राधिकार पत्र

तक बैंक।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित ।—

१ आयातक	को उनके पत्र स०	विनाक
के समर्थ में।		

२ आयातक का बैंक . . . . . उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इडिया, टाकियो, शाच से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी सभरको को येन भुगतान में बारावर संपत्ति जमा करने की अवश्यकता करे। सभरको का सुकार्यी गई धनराशि के बारावर संपत्ति की गणना सार्वजनिक सूचना स० ४-आईटीसी(पीएन)/७६ विनाक १७-१-७६ या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो संमय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी सभरको का भुगतान करने तिथि को धया प्रबलिन परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-मूल्य निकाती के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट विए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशिया या तो रिजर्व बैंक आफ इडिया, नई विल्सी या स्टेट बैंक आफ इडिया तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इडिया की किसी शाखा या इसकी अनुरूप संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीय-कृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-८ (आदेशित और धार्मा) के नाम में और उनके देय दर्शनी हुए के माध्यम से करनी चाहिए। इस सबष्ठ में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना स० २३३-आईटीसी(पीएन)/६८ विनाक ५४-१०-६८, स० १३२-आईटीसी(पीएन)/७१ विनाक ५-१०-७१, स० ७४-आईटीसी(पीएन)/७४ विनाक ३१-५-७४ और स० १०३-आईटीसी(पीएन)/७६ विनाक १२-१०-७६ की शर्तों की ओर विलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह “के डिपोजिट्स एंड एक्वाइज़िशन ४४३ सिविल डिपोजिट्स डिपोजिट्स कार परेजिस एटेसेट्रा एवाइ-परेजिस ग्राउंड एंड फार्म दि गर्वेनमेट आफ जापान कार १९८२-८३ है और विस्तृत लेखा शीर्षक” “छोटे आकार की छड़ों के आयात के लिए जापान से येन १ ५ विलियन अनुदान सहायता है” “येन ५० मिलियन ग्राम एंड फार परेजिस आफ दि जिमनस्टिक एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेट/सीरीजेस कार दि विप्रेज आफ ग्रोमाइंग फिजिकल एज्यूकेशन एंड स्पोर्ट्स इवेलपमेट हून इडिया” है।

जिन मामलों में तुल्य रूपया रिजर्व बैंक आफ इडिया, नई विल्सी या स्टेट बैंक आफ इडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना स० १३२-आईटीसी(पीएन)/७१ विनाक ५-१०-७१ के अनुसार तक जमा किया जाता है उनमें जालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेषण पत्र समृद्धि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी ।—

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वृत्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)  
पहली मजिल, यू सी ओ बैंक विल्डिंग,  
सप्तम मार्ग नं० विल्ली- 110001

~~विस मामले में तुल्य रूपया उपर सकेति सार्वजनिक सूचना दिनांक  
14-10-1968 में यथा उत्तिलिखित दर्शनी हुए द्वारा प्रेषित करना है उसकी  
उपर्युक्त पते पर जर्जी जारी चाहिए। सभी मामलों में, व्याज की  
धरणी अन्धराशी और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है  
बुकाई गई तथा जमा किए गए तुल्य रूपए का पूरा छाँरा इस विभाग  
ओर उसके सं  
को लेजना चाहिए~~

के बैंकर के खर्चों सहित धदि कोई हो तो, वैकिंग सम्प्रदाय समरक इडिया, टोकियो शाच के अन्य खर्चे इडियन बैंक खर्चे और अप्रेस टोकियो शाक्षा द्वारा संघों ही निर्धारित किया जाएगा।

4. भारतीय व्यवसंग, दीक्षियो ।

३. अन्नर सचिव (टी. प.) बालाड रिस मंडालय, आर्थिक कार्य विभाग  
नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE  
IMPORT TRADE CONTROL**

New Delhi, the 28th June, 19<sup>83</sup>

~~Subject: Licensing Conditions for import of  
small size steel bars and rods necessary  
for the transportation thereof to  
ports in India from Japan under  
Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen  
1.5 billion.~~

File No. IPC|23(2)|83.—The terms and conditions governing the licensing conditions for import of small size steel bars services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion dated 1-2-1983 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

**P.C. JAIN, Chief Controller  
Imports & Exports**

Appendix to Ministry of Commerce Public  
Notice No. 21-ITC(PN) 83 dated 28th June, 1983

Licensing Conditions for import of small size steel bars & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion.

## Section I-General Conditions

I(i) The Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion (C&F) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for import of small size steel bars and services necessary for their transportation to ports in India by

the Steel Authority of India Ltd. This grant aid is valid upto 31-3-1984.

I(ii) All banking charges payable to the Bank of India, Tokyo may be remitted through normal banking channels. Payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India.

I(iii) The steel bars and services incidental thereto should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I(iv) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1984".

I(v) The contract value (C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any in no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost & freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I(vi) The purchase contract should be entered in' o only in Japanese Yen with the Japanese nationals.

**Section II.**—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract:

II(i). The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 1st February, 1983 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1982-83 and will be subject to the approval of both the Government.

II(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1982-83.

II(iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II(iv) The Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this pur-

pose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

### Section-III Contract Approval by Governments of India and Japan.

III(i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respect together with two copies of the "Request for issue of A|P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III(ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III(iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form of Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo the importers' Bank in India and the C.A A&A.

III(v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittance to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

### Section IV Responsibility for rupee deposit

IV(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (ii) in Annexure-I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier is deposited into Government of India account as described below :—

The importer i.e. Steel Authority of India Ltd. (SAIL) would deposit the cost of the imported steel bars computed on the basis of the indigenous price of steel reduced by the amount of customs duty paid by it plus 4% of the service charges on C&F value and other charges like handling, railway freight etc. The difference between the C&F value of the imported steel bars and the amount actually deposited by the importer as stated above would be later adjusted in the subsidy payable by the Department of Steel to CAA&A and budgeted for in 1983-84. No interest charges would be payable by the importer on the amount which will be adjusted between the Deptt. of Steel and CAA&A and for the period of difference between the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese supplier and the date of actual rupee deposits made by them with their bankers in India."

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No.8-ITC(PN)76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India Any change in

this regard will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Accounts before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

The Head of Account to which the above rupee deposit should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan" for 1982-83, Grant for purchase of the steel items.

IV(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Banks of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN) | 68 dated 30-8-1968 No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971.

IV(iii) While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury challans :

- Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- Date of payment to the Japanese supplier.
- Total amount deposited.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and

negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

#### Section V Miscellaneous provisions

##### V(i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

##### V(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of steel items under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

##### V (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

##### V(iv) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1982-83 from Japan.

##### V(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

##### V(vi) List of Annexures :

Annexure I—Request for issue of A|P

Annexure II—Form of A|P.

## ANNEXURE I

## “REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY”

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street, New Delhi-110001

Subject : Import of small size steel bars & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid for 1982-83.

Sir,

In connection with the import of steel items from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (c) Brief description of the goods.
- (d) Origin of the goods.
- (e) Gross C & F Value of contract (in Yen).
- (f) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any payable in Indian rupees.
- (g) Net C&F Value (in Yen) for which the A|P is required.
- (h) Number & date of the contract with Japanese Suppliers.
- (i) Name and Address of the Japanese Supplier.
- (j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (k) Expected date of completion of deliveries.
- (l) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(m) Shipment instructions (indicate if transhipment/partshipment permitted or not permitted).

(n) Name and Address of the Importer's bank in India.

Yours faithfully,

## ANNEXURE II

No. F

Govt. of India

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan)

Subject : Import of small size steel bars under Japanese Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1982-83—Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen to M|s. as per details given in the Appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including charges for handling documents, and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any, payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's Bank.

6. No amendment to this A|P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A|P will remain valid upto —————.

Yours faithfully,  
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer \_\_\_\_\_ with reference to their letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

2. Importer's Banker \_\_\_\_\_ They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notices No. 8-ITC(PN)76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that those deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)68 dated 24-10-68, No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)74 dated 31-5-1974 and 103-ITC(PN)76 dated 12-10-76. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposits—Deposits for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from Govt. of Japan for 1982-83' under detailed head "Yen 1.5 billion grant aid for

import of small size steel bars from Japan".

One copy of the challan in original in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

3. In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited along with the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

